लिए उपयुक्त एक-एक माडल पनधाराओं को राष्ट्रीय पनधारा नीति समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । उसके बाद राजकीय समितियां उस मण्डल की शेष परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है । उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायुकीय मण्डलों को वर्षा तोषित क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें से प्रत्येक मण्डल के लिए एक-एक माडल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(ग) परियोजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम-घटकों में मृदा संरक्षण के लिए कृष्य भूमि, अकृष्य भूमि तथा जल निकासी सम्बन्धी उपचार करना तथा वार्षिक फसलों, कृषि वानिकी, चारागाह विकास, पशुधन प्रबंध, घरेलू आय को सृजित करने वाली गतिविधियों को शामिल करके विविध उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहन देना आदि शामिल किया गया है ।

प्रोत्साहन देना आदि शामिल किया गया है ।

3131. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां हैं;

(ख) इन सहकारी समितियों के माध्यम से किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन वस्तुओं का और कितनी-कितनी मात्रा में जिलावार वितरण किया गया ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) 8,600.

(ख) इन सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता ऋण (लघु अवधि, मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि) उर्वरक, बीज कृषि उपस्कर एवं उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण है ।

(ग) विवरण अनुपत्र में है । **[देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र सं. 56]**

**कपास का उत्पादन**

3132. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

**डा. जितेन्द्र कुमार जैन** :

**श्री राम जेठमलानी** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में प्रति-हैक्टेयर कपास उत्पादन दर अलग-अलग है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां कपास का अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादन होता है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अन्तर को समाप्त करने हेतु क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** (क) जी, हां ।

(ख) नौ मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में, कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन पंजाब में सबसे अधिक, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में सबसे कम है । योजना आयोग ने 1991-92 के लिए 241 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुमानित स्तर से वर्ष 1996-97 अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए, कपास की उत्पादकता का अखिल भारतीय लक्ष्य 317 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया है जिसमें विशेषकर कम उपज के क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि करने की व्यवस्था है ।

**State Land use board**

3133. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have accorded approval for the continuation of Central Sector Scheme for strengthening the State Land Use Board during the Eighth Plan;

(b) whether the State Government of Karnataka has submitted a proposal for Centre's approval and release of necessary funds for implemnting the Scheme during 1992-93; and

(c) if so, whether the Central Government would accord its approval for the proposal and release funds expeditiously ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The necessary funds as per the state's entitlement have been released.

**Diversion of Funds Meant for Earth Quack Victims of Uttarkashi**

3134. SHRIMATI VEENA VERMA :

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have initiated an inquiry into the alleged diversion and misuse of the funds meant for distribution amongst the earth quake victims of Uttarkashi, including the funds released by the Centre for the purpose; and

(b) if so, what are the findings thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

3135. [*Transferred to 30th March, 1993*]

**गुजरात में दाल-मिलों की स्थापना**

3136. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के प्रसंस्करण के लिए गुजरात में दाल-मिलों की स्थापना की गयी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय दाल विकास योजना के अंतर्गत पर्याप्त उपबंध किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं ?

**गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 25.25 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1992-93 के दौरान कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार का शेयर 20.13 करोड़ रुपए है। अन्य घटकों के अतिरिक्त, योजना में किसानों द्वारा अधिक से अधिक 1.5 अश्व शक्ति क्षमता के दाल प्रोसेसर की खरीद के लिए राजसहायता प्रदान करने का घटक शामिल है। योजना में दाल मिलों की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है। खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि गुजरात लगभग 1.50 लाख टन दालों का उत्पादन करता है, जिसका परिसंस्करण अधिकतर निजी स्वामित्व वाली मिलों में किया जाता है। दाल मिलिंग लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है यद्यपि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, एस. एस. आई. इकाईयों के रूप में 103 दाल मिलों का पंजीकरण किया गया है।

**Foodgrains for Orissa**

@3137. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether the State Government of Orissa has placed any demand before the Central Government for supply of foodgrains for the year 1993-94;

(b) if so, what are the details of monthly demand and allocation of wheat and rice; and

(c) what are the details of action taken or proposed to be taken to meet the State's demand ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (c) The State Government of Orissa has not yet sent its

@Previously unstarred Question 2294 transferred from 15th March, 1993.